वर्किंग पेपर के महत्वपूर्ण परिणाम

राजस्थान में स्कूल एकीकरण: कार्यान्वयन और अल्पावधि प्रभाव

किसके संबंध में

2018 में, Accountability Initiative (Centre for Policy Research) ने 2014-15 में राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल एकीकरण नीति का अध्ययन किया। राजस्थान भारत में बड़े स्तर पर स्कूलों को एकीकृत करने वाले राज्यों में से एक था। राजस्थान शिक्षा निदेशालय के अनुसार, 2014-15 से 2018-19 तक लगभग 22,000 स्कूलों का एकीकरण किया गया है। हालाँकि, इन स्कूलों में से लगभग 2,500 के लिए, एकीकरण उलट दिया गया (और जानकारी के लिए वर्किंग पेपर के पृष्ट 5 को देखें: www.accountabilityindia.in) I 2018- 19 तक कुल एकीकरण हुए विद्यालयों की संख्या 19,500 थी।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन विश्लेषण के लिए कुछ मुख्य डेटा स्रोतों का उपयोग करता है: 1. यू-डी,आई.एस.ई. (U-DISE) उपलब्ध विद्यालयवार आंकड़े; 2. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार, और 3. स्कूल एकीकरण के लिए राजस्थान सरकार के आदेशों की समीक्षा।

नामांकन, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षक उपलब्धता में परिवर्तन को समझने के लिए, एकीकरण से **पहले और बाद** में स्कूल के विशिष्ट संकेतकों का विश्लेषण किया गया था। इन संकेतकों की तुलना राज्यव्यापी रुझानों से भी की गई थी। अध्ययन में निम्नालिखिक शामिल है:

- ऐसे स्कूल जिनके लिए अगस्त और सितंबर 2014 के बीच एकीकरण के आदेश भेजे गए;
- जिन स्कूलों के लिए समेकन आदेश जून और सितंबर 2016 के बीच भेजे गए।

विस्तृत कार्यप्रणाली के लिए, कृपया वर्किंग पेपर के पृष्ट 9 को देखें: www.accountabilityindia.in I

यह अध्ययन किन चीज़ों को नहीं देखता?

- **सीखने के परिणामों पर प्रभाव**: यू-डी.आई.एस.ई. (U-DISE) में स्कूल-विशिष्ट सीखने के परिणामों पर डेटा की कमी के कारण, इस अध्ययन ने नए एकीकृत हुए स्कूलों में स्थानांतरित होने के बाद छात्रों के सीखने के स्तर पर प्रभाव को नहीं देखा है।

- **आर.टी.ई के स्कूल की दूरी से सम्बंधित मानदंडों का अनुपालन**: कानूनी आरटीई जनादेश को देखते हुए, यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या एकीकृत स्कूल दूरी के मामले में छात्रों के लिए सुलभ हैं। हालांकि, यू-डी.आई.एस.ई. (U-DISE) में स्कूलों की दूरी के आंकड़ों की कमी के कारण हम इसका विश्लेषण नहीं कर सके।

- **छात्रों और माता-पिता का दृष्टिकोण**: यह अध्ययन माध्यमिक डेटा पर निर्भर करता है और माता-पिता या छात्रों जैसे हितधारकों के दृष्टिकोण को कवर नहीं करता है।

परिणाम

- एकीकरण के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों को अन्य प्राथमिक विद्यालयों या माध्यमिक विद्यालयों के साथ एकीकृत किया गया। इसलिए, मॉडल स्कूलों, विशेष रूप से आदर्श स्कूलों (ग्रेड 1-10 या 1-12) के निर्माण में एकीकरण का योगदान है।

- राजस्थान शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार, स्कूलों को बंद करने के दो कारण थे: (1) अपर्याप्त नामांकन; (2) एक ही राजस्व ग्राम के भीतर एक से अधिक प्राथमिक या उच्च-प्राथमिक विद्यालय का होना या एकीकृत होने वाले विद्यालयों की निकटता।

- स्कूल बंद करते समय कम नामांकन 'के नियम का पालन हर बार नहीं किया। 2014 से 2016 में सरकारी आदेश 'कम नामांकन' को परिभाषित नहीं करते हैं। हालांकि, 2017 में जारी किए गए कुछ दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 15 या 30 से कम नामांकन वाले स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा। हमने पाया कि 2014-15 में बंद हुए स्कूलों के लिए, 66 प्रतिशत स्कूलों में औसत नामांकन 50 से अधिक, 2013-14 में। यह संभावित है कि उच्च नामांकन और निकटस्थ स्कूलों का एकीकरण किया गया है।
  - दो वर्षों के एकीकरण- 2014-15 और 2016-17 - में भी अंतर देखा गया है। 2016-17 की तुलना में 2014-15 में एकीकृत स्कूलों का नामांकन काफी ज़्यादा था। इस अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि 2013-14 में बंद किए गए प्राथमिक स्कूलों का औसत नामांकन 78 था, और 2015-16 में 22। यह संभव है कि प्राथमिक विद्यालयों के अन्य प्राथमिक विद्यालयों के साथ (माध्यमिक विद्यालयों के साथ एकीकरण की तुलना में) एकीकरण कम नामांकन से कुछ हद तक प्रेरित था।

- राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों की तुलना में एकीकृत स्कूलों में नामांकन में अधिक गिरावट देखी गई। नामांकन में गिरावट विकलांगता वाले छात्रों के लिए सबसे अधिक प्रतीत होती है, इसके बाद अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र हैं।
  - 2014-15 में एकीकृत हुए विद्यालयों के लिए, हमारे सैंपल में नामांकन में 7 प्रतिशत की गिरावट थी। राज्य में, यह गिरावट केवल 1.4 प्रतिशत थी।
  - 2015-16 और 2016-17 के बीच, जबकि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई, एकीकृत स्कूलों के लिए नामांकन में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। 2013-14 और 2014-15 के बीच, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के नामांकन में एकीकृत स्कूलों में क्रमशः 6.8 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई। राज्य के लिए, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए गिरावट 1.8 प्रतिशत थी, जबकि ST छात्रों के नामांकन में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-17 में प्रवृत्ति समान है।
  - भले ही सैंपल में विकलांगता से प्रभावित छात्रों का अनुपात छोटा था (लगभग 1 प्रतिशत), यह श्रेणी एकीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुई। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में, 2015-16 और 2016-17 के बीच विकलांग छात्रों के नामांकन में 4 प्रतिशत की गिरावट आई। इसकी तुलना में, एकीकृत विद्यालयों में गिरावट की दर 22 प्रतिशत थी। 2014-15 में समेकित स्कूलों के लिए भी इसी तरह का रुझान है।

- एकीकरण के बाद, प्रति विद्यालय शिक्षकों की औसत संख्या में वृद्धि हुई है। दोनों वर्षों में सभी एकीकृत स्कूलों में दो से अधिक शिक्षक थे। प्रति ग्रेड शिक्षकों (TGR) की संख्या में कुछ सुधार हुआ है। TGR में सुधार उन प्राथमिक विद्यालयों के लिए अधिक दिखाई देता है जो 2014-15 और 2016-17 में माध्यमिक विद्यालयों के साथ एकीकृत हुए।

- कुल मिलाकर, यह देखा गया कि छात्रों को एकीकरण के बाद अन्य बेहतर स्कूलों में स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार उनको बाउंड्री वॉल, बिजली कनेक्शन, पुस्तकालय और खेल के मैदान जैसी बेहतर सुविधाओं का प्रावधान मिला।

एकीकरण के बारे में

- एकीकरण एक या एक से अधिक स्कूलों को 'बंद' करना और दूसरे स्कूल के साथ समेकन करना है। इसके तहत:
  - सभी भौतिक और मानव संसाधन छात्रों और शिक्षकों सहित एकीकृत स्कूल में स्थानांतरित किए जाते हैं;
  - बंद 'स्कूल अब एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मौजूद नहीं होती, भले ही इसकी इमारत का प्रयोग हो;
  - बंद 'स्कूल का कोई विशेष यू-डी.आई.एस.ई. (U-DISE) कोड नहीं होता।

- स्कूलों को एकीकरण क्यों किया गया? इसका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करना था। कई सरकारी अधिकारियों ने इसका उल्लेख किया, और समग्र शिक्षा वार्षिक कार्य योजना और बजट में कुशल संसाधन उपयोग के लिए एकीकरण के उपयोग का उल्लेख है। जब कम नामांकन वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ एकीकृत किया जाता है, तो प्रत्येक ग्रेड के लिए शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार, जब राज्य सरकारों के साथ सीमित संसाधनों पर विचार करके छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में एकीकृत किया जाता है, तो बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

Accountability Initiative के बारे में:

Accountability Initiative एक अनुसंधान समूह है जो 2008 से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने पर काम कर रहा है। हमने भारत में कुशल सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को प्रभावित करने वाली राज्य क्षमताओं और कारकों पर साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के माध्यम से ऐसा किया है। हमने बहु-क्षेत्रीय सामाजिक विषय: जैसे शासन प्रक्रिया और बजट पर अध्ययन किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों को हमने बारीकी से देखा है। हम 5 राज्यों - बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कार्यरत हैं।

हमारी कोशिश उत्तरदायी शासन को सक्षम करने की है। हमारा मानना है कि उत्तरदायी शासन हासिल किया जा सकता है यदि सरकारी संस्थान पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से बनाए जाएं और नागरिक मांगों के प्रति जवाबदार हों। इसके साथ ही जागरूक नागरिक की भूमिका इस जवाबदेही व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण है।

हम Centre for Policy Research का हिस्सा हैं, जो भारत की प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंकों में से एक है।

वर्किंग पेपर यहाँ से डाउनलोड करें:
www.accountabilityindia.in/publication/school-consolidation-in-rajasthan-implementation-and-short-term-effects/